अपराह्न 12.15 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

लेबनान की स्थिति तथा भारतीयों को वहां से निकालना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री ने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर स्वत: वक्तव्य देने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद लेबनान में मौजूदा हालात से वाकिफ हैं। इस संबंध में सदस्यों की चिंता को देखते हुए, मैं सदन को वहां के मौजूदा हालात और उत्पन्न हुई स्थिति पर हमारी प्रतिक्रियाओं विशेषकर, भारतीय नागरिकों जो लेबनान में बढ़ते संकट से प्रभावित हुए हैं, को मदद देने हेतु हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पश्चिम एशिया हमारा विस्तृत पड़ोस है और उस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से हमारी सुरक्षा और हमारे महत्वपूर्ण हित प्रभावित होते हैं। हम लेबनान-इस्राइल सीमा के आस-पास इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष बढ़ने से बहुत अधिक चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों से इस क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है और स्थिति काफी नाजुक हो गई है।

12 जुलाई को भारत में हिजबुल्ला संगठनों द्वारा दो इस्राइली सैनिकों के अपहरण की निंदा की थी और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। कम से कम देश के प्रधान मंत्री के प्रति तो सम्मान प्रकट कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति से आइए। आपका स्वागत है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप वापस आ गए हैं।

डा. मनमोहन सिंह: इसके साथ ही, हमने इस्राइल द्वारा अत्यधिक और अंधा-धुंध सैन्य प्रतिशोध की भी कड़े शब्दों में निंदा की थी। हमने विशेष तौर पर चिंता व्यक्त की थी कि इस्राइली सैन्य बलों की कार्रवाई से निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं, की हत्याएं हुई हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है जिससे और भी अधिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हम उन हमलों की भी निंदा करते हैं जिनमें लेबनान में तैनात 4 संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की मौत हो गयी है।

भारत ने फिलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (पैलेस्टियन नेशनल अथारिटी) के मंत्रियों और फिलस्तीनी विधायी परिषद (पैलेस्टियन लेजिस्लेटिव काउन्सिल) के सदस्यों की पूर्णत: अनुचित गिरफ्तारी और उन्हें बंदी बनाए रखने की भी निंदा की है। फिलस्तीनी लोगों के विधिवत् चुने गए प्रतिनिधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

ऐसे देश, जिसका गृह-युद्ध के दो दशकों बाद बड़ी मेहनत से पुनर्निर्माण हुआ है, के विध्वंश का कोई भी सभ्य राष्ट्र समर्थन नहीं कर सकता। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि लेबनान की सरकार द्वारा जारी की गई अपील के जवाब में, सरकार ने लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए मानवीय और राहत प्रयासों में 10 करोड़ रुपए का अंशदान देने का निर्णय लिया है।

हमारी राय में, वहां पर लड़ाई तुरन्त बंद होनी चाहिए ताकि लेबनान की बर्बादी रुक सके और मानवीय आधार पर मदद पहुंचाई जा सके। सभी तरफ से तत्काल हिंसा रुकनी चाहिए और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। कूटनीति के कामयाब होने से दीर्घकालीन हल निकल सकेगा जिसमें क्षेत्र की सभी पार्टियां शामिल हों और उनकी वाजिब चिंताओं पर ध्यान दिया जाए ताकि स्थिति का व्यापक तौर पर और बातचीत के जरिए समाधान हो सके।

उस देश में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण हमारी मुख्य चिंता रही है। 17 जुलाई को सुरक्षा स्थिति के और बिगड़ने का पूर्वानुमान लगाते हुए, सभी भारतीय नागरिकों विशेषकर जो दक्षिणी लेबनान में रह रहे हैं, को सलाह दी गई थी कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में उचित एहतियात बरतें। समाधान करने के लिए सलाह-मशविरे किए गए कि लेबनान में बसे हमारे नागरिकों, जो लौटने के इच्छुक हैं, को किस तरह भारत सुरक्षित वापस लाया जाए। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे बेरूत में भारतीय दूतावास जिसे वहां उत्पन्न स्थिति के संबंध में आवश्यक परामर्श और अद्यतन जानकारी मुहैया कराने के लिए हिदायतें दी गई हैं, के संपर्क में रहें।

चूंकि बेरूत हवाई अड्डा बंद था और बेरूत और दमिस्क के बीच सड़क मार्ग असुरक्षित था, इसलिए यह महसूस किया गया कि भारतीय नागरिकों को बेरूत बंदरगाह के जरिए निकालना सबसे उपयुक्त रहेगा। चार भारतीय नौसेना पोतों-आई.एन.एस. मुंबई, आई.एन.एस. ब्रह्मपुत्र, आई.एन.एस. बेतवा और आई.एन.एस. शक्ति

*ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-4500/2006

[डा. मनमोहन सिंह]

जो लाल सागर क्षेत्र में थे, को भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने में मदद के लिए बेरूत भेजा गया।

भारतीय नागरिकों की निकासी का पहला प्रयास 21 जुलाई, 2006 को किया गया। 598 भारतीय नागरिकों को तथा मानवीय आधार पर, नेपाल, लेबनान और श्रीलंका के नागरिकों को आई.एन.एस., मुंबई द्वारा बेरूत से निकालकर साइप्रस में लरनाका पहुंचाया गया। लरनाका से, एयर इंडिया ने उन भारतीयों को मुम्बई और चेन्नै पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों का प्रबंध किया।

बेरूत से भारतीयों की दूसरी निकासी 24 जुलाई को की गई। इसमें 887 लोग थे जिनमें 784 भारतीय, 41 नेपाली, 57 श्रीलंका और 5 लेबनानी नागरिक थे। सभी भारतीय नागरिकों और नेपाल तथा श्रीलंका के नागरिकों को लरनाका से हवाई जहाज द्वारा भारत पहुंचाया गया और वे सुरक्षित पहुंच गए हैं। निकासी का तीसरा चरण 26 जुलाई को पूरा किया गया जिसे मिलाकर बेरूत से निकले लोगों की कुल संख्या 1870 है जिनमें 1687 भारतीय नागरिक हैं।

हमारा अनुमान है कि लड़ाई शुरू होने के समय लगभग 12,000 भारतीय नागरिक लेबनान में थे। उनमें अधिकतर अर्द्ध-कुशल और अकुशल कामगार हैं जो खेतों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश लोगों ने लेबनान छोड़ने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ लोगों ने वहीं रहने का निश्चय किया है। कुछ लोग संचार-व्यवस्था में व्यवधान के कारण बेरूत नहीं पहुंच पाए होंगे। हमें अब तक बेक्का घाटी में एक ग्लास फैक्ट्री पर हुए हवाई हमले में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है।

हमारा दूतावास बेरूत में अभी काम कर रहा है और वह विभिन्न संगठनों और एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए हुए है जिनसे भारतीय नागरिक संबद्ध थे। फिलहाल, हमारे नौसेना पोत इस क्षेत्र में बने रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भारतीय नागरिकों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेबनान में हालात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों की आगे और निकासी की योजना बनाई जाएगी।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक हिस्से के रूप में, हमारी 672 भारतीय अधिकारियों और सैनिकों की एक टुकड़ी भी है। हमारे शांति-सैनिक सुरक्षित हैं, वे इस समय अपनी बैरकों में हैं।

मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने कितनी मुस्तैदी से और सफलतापूर्वक मुसीबत में पड़े हमारे साथी नागरिकों की मदद के लिए कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हताहतों को आपकी उपस्थिति में मुआवजा दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कल मैंने आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कृपया बैठ जाए। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाए। मुझे अत्यन्त खेद है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम प्रधान मंत्री जी के बहुत आभारी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल श्री डी.वी. सदानन्द गौडा के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा के लिए अनुमति देने को तैयार हूं। अब कुछ और नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री सदानन्द गौडा के वक्तव्य को रिकार्ड किया जाएगा। मैं चर्चा की अनुमति प्रस्ताव के माध्यम से दूंगा। प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं यहां वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को आरम्भ नहीं करने दूंगा। नियम मुझे इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा को अपराह्न 1.30 बजे तक स्थगित किया जाता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।